International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 1; Issue 4; July 2016; Page No. 54-57

चीन : ऐतिहासिक विरासत और राजनीतिक परम्पराएं

डॉ0 सुमन यादव

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी के पहले दशक से ही चीन में क्रान्तिकारी हलचल आरम्भ हुई। यह घटनाक्रम साम्यवादियों के प्रभावशाली होने के काफी पहले आरम्भ हो गया। सनयात सेन की कुमिनतांग पार्टी की स्थापना, 1911 की क्रान्ति आदि इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण घटनाएँ है। गणराज्य की स्थापना के बाद गृह युद्ध का चरण आरम्भ हुआ, जिसकी परिणति जापानी सैन्यवाद–विस्तारवाद से प्रेरित मंचूरियाई हस्तक्षेप में हुई। इन ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराने का उद्देश्य यह है कि यह बात स्पष्ट हो सके की चीनी राजनीति में व्यापक क्रान्तिकारी उथल–पुथल, अस्थिरता और हिंसक परिवर्तन कोई चीज नही। चीनी सरकारें, वे चाहे साम्रज्यवादी हों, गणतन्त्रीय या साम्यवादी, इन सबका तालमेल चीन के वैदेशिक सम्बन्धों के निर्वाह के साथ लगभग अनायास बिठाती रही है। माइकल हन्ट ने चीनी विदेश नीति के ऐतिहासिक उत्तराधिकार के बारे में लिखा है कि चीन के वैदेशिक सम्बन्धों की एक नहीं, बल्कि अनेक परम्पराएँ (वर्तमान शासक इन सभी के समान रूप से उत्तराधिकारी बने) हैं। 'इनमें बर्बर बल प्रयोग का स्वरूप मिलता है और गुप्त सन्धि–समझौतों का भी; व्यापरिक व सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अनुभव का उल्लेख भी; दूसरो पर अपना प्रभुत्व थोपने की चेष्टा है तो विजेता के समक्ष समर्पण व उसके पास सहकार की तत्परता भी। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चीन के विषय में कहा था कि ''वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा, तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुप्तावस्था से जागने लगा और यह नितान्त सत्य है कि उसके जागरण ने विश्व को एक बार हिला दिया है। चीन में साम्यवाद की स्थापना ने एशिया में वैसी ही समस्या उत्पन्न कर दी है, जैसी समस्याएं 1917 ई. में सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थीं। चीन की परम्परा है और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गत कुछ वर्षो में चीन ने अपनी इसी विस्तारवादी नीति का परिचय दिया।

चीनः भूमि और लोग – वृहत्तर चीन एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कोरिया की सीमा पर यालू नदी से लेकर वियतनाम की सीमा पर पेलुम नदी तक इसका विस्तार है। इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत की श्रेणियां और उत्तर–पूर्व से सोवियत रूस है। हिमालय पर्वत चीन को भारत, भूटान और नेपाल से अलग करता है। चीन की राजधानी पेइचिंग है। अब क्षेत्र की दृष्टि से भी चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 97.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह समस्त क्षेत्र 34 प्रान्तों में बंटा हुआ है। पिछले लगभग दो दशक से चीन जनसंख्या नियन्त्रण के कार्यक्रम को अपना रहा है। पिछले दस वर्षो में जनसंख्या नियन्त्रण के इस कार्यक्रम में गति आयी है और भारतीय अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीन जनसंख्या वृद्धि पर लगभग रोक लगाने में सफल रहा है। यह विशाल क्षेत्र और जनसंख्या चीन को युद्ध तथा विस्तारवादी नीति अपनाने और विश्व राजनीति में अग्रणी स्थान प्राप्त करने की दशा में प्रेरित करती रही है। सोवियत रूस की भांति चीन एक बहु–जातीय देश है, जिसमें हान (Hann) अथवा चीनियों की प्रमुखता है। पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 93 प्रतिशत हान जाति है। अन्य मूल जातियों में ये मुख्य है। मंगोल, हुई, तिब्बती, कोरियन, मंचु आदि। चीन के विभिन्न जनसमूहों में अनेक प्रकार की विविधताएं पायी जाती है, फिर भी उनमें एक भाषा व संस्कृति तथा अन्य कारणों से एकरूपता है। सभी जातियों को एक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण सांस्कृति स्वायत्तता प्रदान कर संविधान ने भी इस एकरूपता को बनाये रखने में योग दिया है। चीन की मुख्य भाषा चीनी है, यद्यपि 150 अन्य भाषांए और बोलियां भी चीन में प्रचलित है। चीन की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या साक्षर है। भारत के ही समान चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसमें लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है। खनिज पदार्थो का चीन में बाहुल्य है। चीन के प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात से बनी हुई मशीनें, मोटरें, जलयान, सीमेण्ट, कपड़ा, कागज और रबड़ के जूते इत्यादि है। चीन ने अपना लक्ष्य 1990 ई0 तक विश्व के प्रथम श्रेणी के औद्योगिक राष्ट्र की स्थिति को प्राप्त करना निर्धारित किया था, लेकिन चीन की परिस्थितियां इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत अधिक सहायक नहीं है और विशाल क्षेत्र तथा अत्यधिक जनसंख्या वाले इस देश को आधुनिक औद्योगिक कृषक राज्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक लम्बा रास्ता तय करना होगा। अभी तो स्थिति यह है कि मौसम के देवता की थोड़ी–सी अकृपा से लाखों चीनी भयंकर भूख के कगार तक पहुंच जाते हैं।

संवैधानिक विकास – चीन एक अत्यन्त प्राचीन देश है जिसकी संस्कृति और सभ्यता अपना विशिष्ट स्थान रखती है। चीन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए 19वीं सदी से संवैधानिक विकास का अध्ययन किया जा सकता है। 19वीं सदी से प्रारम्भ होकर बीसवीं सदी के मध्य तक का चीन का संवैधानिक और राष्ट्रीय इतिहास साम्राज्यवादी कुचक्रों का ही परिचय देता है।

'अफीम युद्ध' और चीन में साम्राज्यवादी शक्तियों **का हस्तक्षेप** – इस समय चीन यूरोप के देशों की तुलना में अधिक उन्नत था। चीन की चाय, रेशमी कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तनों की यूरोप में बड़ी मांग थी। लेकिन इनके बदले में चीनी किसी भी यूरोपियन माल को खरीदने के लिए उत्सुक नहीं थे। प्रारम्भ में यूरोपीय व्यापारी चांदी और सोने के सिक्कों में भुगतान करते थे लेकिन अधिक समय तक ऐसा नहीं किया जा सकता था, अतः 18वीं सदी में ब्रिटेन ने भुगतान की समस्या का नया हल निकाला। वे हिन्दुस्तान में अधिक से अधिक अफीम का उत्पादन कराकर इसे चीन में बेचने लगे और अफीम के इस तस्कर व्यापार से ब्रिटिश पूंजीपतियों को बहुत लाभ होने लगा। कैण्टन के भ्रष्ट अधिकारी भी तस्कर व्यापार में ब्रिटिश कम्पनियों की मदद करने लगे। चीन की सरकार ने प्रारम्भ में विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये।

लेकिन थोड़े समय बाद ही ब्रिटिश षड्यन्त्र की गम्भीरता को अनुभव किया गया और चीन सरकार ने अफीम लाने वाले ब्रिटिश जहाजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार इससे रूष्ट हो गयी और 1839–42 ई0 में चीन और ब्रिटेन में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। ब्रिटेन ने चीन को युद्ध में पराजित कर चीन पर पहली 'असमान सन्धि' (Unequal Treaty) लादी। इसके बाद चीन को संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के साथ भी इस प्रकार की 'असमान सन्धियां' करनी पड़ी। इन्हें 'असमान सन्धि' इस दृष्टि से कहा जाता है कि इनमें चीन के सम्मान और हितों की नितान्त उपेक्षा की गयी और हैरोल्ड सी. हिण्टन के मतानुसार, ''इन सन्धियों के परिणमस्वरूप चीन के सम्प्रभुता पर गम्भीर प्रतिबन्ध लगा दिये गये।'' इन सन्धियों की शर्तो के कारण चीन के उद्योग धन्धों को बहुत हानि पहुंची।

असफल ताइपिंग विद्रोहऔर चीन का भारी शोषण – साम्राज्यवादी देशों में भीषण शोषण की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी और यह 1850–64 ई0 के ताइपिंग विद्रोह के रूप में हुई जो वस्तुतः चीन की पहली राष्ट्रीय और जनतन्त्रीय क्रान्ति थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। 1892 ई0 में साम्राज्यवादी शाक्तियों ने चीन को औपनिवेशिक प्रभाव क्षेत्रों में बांट लियां मंचूरिया रूस के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। शान्तुंग पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया, जापान ने फूकियन को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया, दक्षिण–पूर्वी चीन फ्रांस के हिस्से में आया और मुख्य चीन की लगभग आधी भूमि (यांग्ट्सी और ह्वांगहो के मैदान) ब्रिटेन के हिस्से में आ गयी। प्रत्येक साम्राज्यवादी देशको अपने प्रभाव क्षेत्र में पूंजी के निवेश (Investment) और संचार के विकास का लगभग एकाधिकार प्राप्त हो गया। अमरीका भी इस आर्थिक शोषण में शामिल था। इस स्थिति के सम्बन्ध में महान् चीनी सनयात सेन ने कुछ रोष भरे शब्दो में कहा था कि ''इस प्रकार चीन किसी एक देश का उपनिवेश या अर्द्ध–उपरिवेश तो नहीं बना, वरन् वह कई देशों का एक संयुक्त उपनिवेश बन गया।''

बाक्सर विद्रोह – 1900 ई. में चीन में 'बाक्सर विद्रोह' जिसका उद्देश्य चीन में विदेशी प्रभाव और मांचू वंश का अन्त कर एक गणराज्य की स्थापना करना था। इस विद्रोह में अनेक विदेशी और ईसाई मारे गये। इस विद्रोह के पीछे राष्ट्रवादी नेता सनयात सेन का हाथ था, जो 1885 ई0 में चीन छोड़कर अमरीका चले गये थे और वहीं से राष्ट्रवादियों का नेतृत्व कर रहे थें। सभी विदेशी शक्तियों ने इस विद्रोह का संगठित होकर सामना किया और उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दीं। विद्रोह की असफलता से चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभाव और अधिक बढ़ गया।

1911 ई0 की क्रान्ति और प्रथम गणराज्य की स्थापना – चीन में यद्यपि बाक्सर विद्रोह को दबा दिया गया, परन्तु राष्ट्रीय भावनाएं ज्यों–की–त्यों बनी रहीं। 1905 ई0 में जापान के हाथों सोवियत रूस की पराजय ने चीन के राष्ट्रवाद को नयी प्रेरणा और शक्ति प्रदान की। इस क्रान्ति के प्रमुख आधुनिक चीन के निर्माता सनयात सेन थे। उनके तीन सिद्धान्तों–जन राष्ट्रवाद, जन प्रजातन्त्र और जन आजीविका–से प्रभावित होकर चीन के लोगों ने डॉ. सेन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 1911 ई0 की क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति से मांचू वंश के शासन का अन्त हो गया, क्रान्तिकारियों की एक सभा दिसम्बर 1911 ई0 को नानकिंग नगर में हुई और इस सभा ने चीन को एक गणराज्य घोषित कर दिया। डॉ. सनयात सेन को इस सभा ने अस्थायी राष्ट्रपति चुन लिया लेकिन समस्त चीन में सनयात सेन का प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका और चीन प्रधानमन्त्री युवान शीहकाई ने दक्षिण चीन में एक और गणराज्य स्थापित कर लिया। डॉ. सेन ने चीन की एकता को बनाये रखने के लिए युवान के पक्ष में अपना त्यागपत्र दे दिया।

कोमिन्तांग पार्टी की स्थापना – युवान शीहकाई ने चीन की स्थिति में सुधार करने के लिए इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा जापान से ऋण लेने शुरू कर दिये। युवान का यह कार्य 1911 ई0 की क्रान्ति के घोषित सिद्धान्तों के विरूद्ध था, सनयात सेन के अनुयायियों ने इसका घोर विरोध किया और डॉ. सनयात सेन और उनके अनुयायियों ने अपने आप को कोमिन्तांग पार्टी में संगठित कर दिया, जो एक राष्ट्रीय दल था। युवान शीहकाई को कोमिन्तांग पार्टी और उसके बाद जापान के हाथों अपमानित होना पड़ा और जून 1916 ई0 में युवान शीहकाई की मृत्यु हो यगी। उसके पश्चात कोमिन्तांग पार्टी का नेता ली युवान हंग राष्ट्रपति बन गया। इस तरह से समस्त चीन कोमिन्तांग पार्टी के नेतृत्व में संगठित हो गया।

कोमिन्तांग – कोमिण्टर्न समझौता (Knomintang-Comintern Alliance) – 1917 ई0 में पूर्व सोवियत संघ में समाजवादी क्रान्ति हो गयी। चीन साम्यवादी दल रूस के मार्ग दर्शन में अपना कार्य करने लगा। डॉ. सनयात सेन के नेतृत्व में जो कोमिन्तांग पार्टी गठित हुई थी, वही चीनी साम्यवादी दल का विरोध करने लगी। कोमिन्तांग पार्टी एक ओर साम्यवादी दल का विरोध सहन कर रही थी। 1923 ई. में सनयात सेन ने स्थिति को समझ कर पूर्व सोवियत संघ और कामिण्टर्न से समझौता कर लिया। लेनिन इस समझौते के आधार पर चीन में राष्ट्रीय क्रान्ति को सफल बनाकर साम्राज्यवादी शक्तियों को आघात पहुंचाना चाहता था और डॉ. सेन की रूचि रूस से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में थी। समझौते के अन्तर्गत चीन में पूर्व सोवियत संघ के सैनिक और राजनीतिक सलाहकार भी आये। 1923 ई. में डॉ. सेन ने चीनी साम्यवादियों से बातचीत करके एक समझौता किया और साम्यवादियों को अपने दल का सदस्य बनने की आज्ञा दे दी। साम्यवादियों ने जन समर्थन प्राप्त और दल को अन्दर से क्रान्तिकारी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से कोमिन्तांग दल में प्रवेश किया। इस सन्धि के अन्तर्गत ही डॉ. सनयात सेन के विश्वासपात्र सहयोगी च्यांग काई शेक सोवियत संघ में प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके अन्तर्गत ही 'वम्पाओ सैनिक अकादमी' (Whimpao Military Academy) स्थापित की गयी जिसके मुख्य अधिकारी च्यांग थे।

साम्यवादियों द्वारा सत्ता का अधिग्रहण – 1945 ई0 में जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ, तब चीन औपचारिक रूप से च्यांग काई शेक और उनके कोमिन्तांग दल के नियन्त्रण में था, लेकिन देश की वास्तविक शक्ति साम्यवादियों के हाथ आ गयी थी। इस समय तक 10 लाख व्यक्तियों की लाल सेना का गठन हो चुका था और 27 'मुक्त क्षेत्र' स्थापित किये जा चुके थे। कोमिन्तांग और साम्यवादी दल के बीच समझौते और एक मिली–जुली सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया गया, किन्तु इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई और 1946 ई0 में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष प्रारम्भ होता जा रहा था। न केवल ग्रामीण जनता, वरन् शहरों के बुद्धिजीवी और विद्यार्थी भी इसके विरूद्ध हो गये थे। संयुक्त राज्य अमरीका से बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय और सैनिक सहायता प्राप्त होने के बावजूद कोमिन्तांग शासन साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को नहीं रोक सका। अन्त में, 1949 ई0 में कोमिन्तांग शासन का पतन हो गया, जबकि च्यांग काई शेक ने अपनी सेना के प्रमुख अंगों के साथ चीन की मुख्य भूमि को छोड़कर फारमोसा टापू में शरण ली। साम्यवादियों ने शासन पर अधिकार कर लिया और अक्टूबर, 1949 ई0 को माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गयी।

1982 ई0 का संविधान (नया संविधान या वर्तमान संविधान)

पृष्ठभूमि – 1976 ई0 में माओं की मृत्यु के बाद चीन की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में माओ के योगदान पर पुनर्विचार किया जाने लगा और 1978 ई. के बाद सत्तारूढ़ शासक वर्ग के द्वारा विशेष रूप से अनुभव किया गया कि माओ का रूढ़िवादी साम्यवादी का मार्ग आज की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसके स्थान पर प्रगतिशील साम्यवाद तथा विकसित औद्योगिक तकनीक को अपनाये जाने की आवश्यकता है। 1978 ई0 के संविधान पर विचार के लिए एक 'पुनरीक्षण समिति' स्थापित की गयी थी। इस समिति के उपाध्यक्ष पेग झेन ने 'नेशनल पीपुल्स कांफ्रेंस' (चीन की संसद) के समक्ष नये संविधान पर अपनी रिपोर्ट पेश की और 4 दिसम्बर, 1982 ई0 को चीन का नया संविधान स्वीकृत किया गया। संविधान के अनुसार, देश में शोषक वर्ग समूल नष्ट कर दिया गया है तथा वर्ग–संघर्ष अब समाज में नहीं है। यह विचार माओत्से तुंग के उस विचार से बिल्कुल हटकर है जिसमें सतत् क्रान्ति की बात कही गयी थी। झेन ने सांस्कृति क्रान्ति को एक बड़ी गलती बताकर यह स्पष्ट कर दिया कि नया नेतृत्व माओवाद से पूरी तरह विमुख हो गया है। चीन में 1949 ई0 में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद यह चौथा संविधान लागू किया गया है। चीन का 1954 ई0 का संविधान रूसी ढांचे पर निर्मित था। चीनी और सोवियत संघ के संविधान की तुलना करते हुए एम. ब्रैशन ने लिखा है कि सोवियत संघ और चीन की संसदें केवल मोहर लगाने वाली संस्थाएं थीं। कालान्तर में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई और इसका प्रमुख कारण 1966–69 ई0 के बीच की सांस्कृतिक क्रान्ति की उपलब्धियों को संवैधानिक जामा पहनाना था। फलस्वरूप 1954 ई. के संविधान में अनेक परिवर्तन किये गये और इनका मुख्य उद्देश्य दल के केन्द्रीकृत नेतृत्व का सरकारी ढ़ाचे पर वर्चस्व स्थापित करना था। 1975 ई0 तथा 1978 ई0 के संविधान संक्रमणकालीन सिद्ध हुए। इनका उद्देश्य एक स्वतन्त्र और अपेक्षाकृत वृहत औद्योगिक और आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना था। 1980 ई0 से ही चीन एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, किन्तु कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी बन सके।

आज चीन आधुनीकिकरण और उदारीकरण तथा बहुत धीमी गति से ही सही, लेकिन लोकतन्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन की राज व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वोच्च व्यक्ति हू जिन्ताओं है। कम्यूनिस्ट पार्टी के 17वें सर्वोच्च सम्मेलन में हू जिन्ताओ को चीन की राजनीति के सर्वोच्च पद, कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर दूसरी बार निर्वाचित किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति के रूप में हू जिन्ताओ का यह दूसरा कार्यकाल है। आज समस्त विश्व आर्थिक संकट के घेरे में है, चीन भी इस स्थिति से प्रभावित है लेकिन अन्य देशों की तुलना में निश्चित रूप से कम प्रभावित है। चीन विश्व व्यवस्था में अपने लिए महाशक्ति प्राप्त करने की दिशा में तीव्र गति से और निरन्तर आगे बढ़ रहा है। चीन के समबन्ध में केवल दो बातें अखरने वाली है। प्रथम, उदार लोकतन्त्र का लगभग अभाव, सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार और मानवाधिकारों का हनन। द्वितीय, चीन आज भी विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है कभी प्रकट रूप में और कभी अप्रकट या गुप्त रूप में। राष्ट्रीय अहंकार और विदेशियो के प्रति तिरस्कार के अतिरिक्त चीनी विदेश नीति की दो और प्रमुख विशेषताएँ है। एक, ऐतिहासिक युग में चीनी सैनिक शक्ति के वृहत्तम विस्तार को चीनी आपनी भौगोलिक सीमा के रूप में परिभाषित करते है और इस खोई जमीन को वापस पाना उनकी विदेशी नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसी कारण सोवियत संघ और भारत के साथ चीन के सीमा विवाद विस्फोटक बने है। इसके साथ जुड़ा दूसरा पहलू विदेशों में रहने वाले चीनी वंशजों (प्रवासी चीनी) का है। इन्हें चीन अपना नागरिक मानता है और इनके हित रक्षण की जिम्मदारी स्वीकार करता है। मलेशिया, इण्डोनेशिया, बर्मा जैसे देशों के साथ चीनी सम्बन्धों में तनाव इसके कारण घटता–बढ़ता रहा है। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में हांगकांग, मकाऊ जैसे स्थानों को चीन ने गँवाया था। उन पर अपना अधिकार फिर से करने की इच्छा भी जनवादी चीन में बलवती रही है।

विश्व राजनीति में चीन का महत्व (Importance of China in World Political) – औपनिवेशिक काल में चीन की आन्तरिक दुर्बलता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका लगभग नगण्य थी। इसका पूरा दोष चीनी असमर्थता पर नहीं डाला जा सकता। इन वर्षो में औद्योगिकीकरण और साम्राज्यवाद के सन्निपात से यूरोपीय ताकतों को चुनौती दे सकना किसी और के लिए सहज नहीं था। बाद में, जब जापान ने चीन को दबाना आरम्भ किया तो उसकी सफलता का रहस्य भी पश्चिमी तौर–तरीके का आधुनिकीकरण था। 1945–49 ई0 के अन्तराल ने इस स्थिति को नाटकीय ढ़ग से बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान कम–से–कम एक दशक के लिए चीन के सन्दर्भ में निष्क्रिय हो गया। दूसरी ओर साम्यवादियों की शक्ति में वृद्धि के साथ दशकों बाद चीन का राजनीतिक एकीकरण सम्पन्न हुआ तथा उसका राष्ट्रीय गौरव पुनः लौट सका। माओ के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार ने कड़े अनुशासन को लागू किया और भ्रष्टाचार का उन्मूलन आरम्भ किया। विचारधारा में साम्य के कारण सोवियत संघ के साथ उसका सामरिक गठबन्धन हो सका और अफ्रो–एशियाई भाईचारे के आधार पर उपनिवेशवाद–विरोधी रवैया अपनाकर चीन ने अपने पक्ष में व्यापक जनमत तैयार किया। इन राजनयिक उपलब्धियों के कारण सैनिक और आर्थिक संसाधनो के अभाव में भी सत्ता ग्रहण करने के बाद चार–पाँच वर्ष में बांडुग सम्मेलन तक चीन अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर चुका था। चीन के अपनी शक्ति का आधार मजबूत करने के लिए इन तात्कालिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त एक दूरदर्शी कार्यक्रम अपनाया। शीत युद्ध के पहले चरण में सोवियत समर्थन के कारण उभरी सामरिक स्थिति भले ही निरापद रह सकी, किन्तु चीनी नेता इस बात को भलीभाँति समझते थे कि वैदेशिक मामलों में अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए उन्हें परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में आत्म निर्भर होना पड़ेगा। जब सोवियत संघ ने इस मामले में उदासीनता दर्शायी तो आर्थिक विकास की बलि देकर भी चीनियों ने 1964 ई0 में परमाणु बम की क्षमता हासिल कर ली परमाणु बिरादरी में बलपूर्वक प्रवेश कर चीन ने अपनी सामर्थ्य, महत्वाकांक्षा तथा मनोबल को एक साथ प्रमाणित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 कुष्ण कुमार मिश्र–भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण, पृ0सं0 1, क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1992
2. Dr. Bindra SS. India and her neighbours, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1984, 17.
3. Gilchrist RN. Principles of Political Science, Orient Longman, New Delhi. 1975, 680.
4. Muhammad Munier. From Jinnah to Zia, Akbar Publishing House, Delhi. 1981, 1.
5. D.G.A. Khan – Disintegration of Pakistan, Meenakshi Parkashan, Meerut, 1985, 1.
6. डॉ0 कृष्ण कुमार मिश्र–भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण, क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1992, पृ0सं0 14।

7. The New Encyclopaedia Britannica, Helen Hemingway Benton Publishers, Chicago. 1973; 74:892.
8. DGA. Khan Disintegration of Pakistan, Meenakshi Parkashan, Meerut. 1985, 1.
9. Dr. SS. Bindra India and Her neighbours, Deep & Deep Publications, New Delhi. 1984, 17.